''नक्सलवादः ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि कारण एवं समाधान''

डा0 प्रवीण कुमार
एसो0 प्रोफे0, समाजशास्त्र विभाग, एस0डी0 (पी0जी0) कॉलेज, गाजियाबाद

सारांश

पश्चिम बंगाल में नेपाल और बंगला देश (तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान) की सीमा पर स्थित गाँव नक्सलवाडी के नाम पर इस आन्दोलन का नाम नक्सलवाद पड़ा यहाँ 25 मई को चारू मजुमदार और कानू सायाल के नेतृत्त्व में आदिवासी संथालों ने भू–स्वामियों के शोषण के खिलाफ हथियार उठा लिए थे इस छोटे से गाँव से शुरू हो कर यह संघर्ष जंगल में आग की तरह निरंतर दूर–दराज तक फैलता चला गया। 1969 में कमुनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी–लेनिन वादी/माले) की स्थापना नें इस आन्दोलन को वैचारिक शक्ति प्रदान की इस आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। खेत जोतने वालों को जमीन पर हक दिलाना, विदेशी पूँजी की शक्ति को समाप्त करना तथा वर्ग संघर्श करना यह आन्दोलन चीन के महान नेता माओत्से तुंग की विचार धारा से पूर्णतः प्रभावित है जो वर्ग संघर्ष और छापामार प्रणाली में विश्वास करता है साथ ही शोषित एवं पीड़ित तबको को एक नई सामाजिक आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था का सपना दिखाता है। इस प्रकार यह आन्दोलन केवल कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि देश की लोक तांत्रिक व्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है इस समस्या से देश के 20 राज्यों के 220 जिले लगभग बुरी तरह प्रभावित हैं।

महत्वपूर्ण शब्दः *नक्सलवाद, शोषण, संघर्ष, सामाजिक*

शोधपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

डॉ0 विनोद कुमार, ''नक्सलवादः ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि कारण एवं समाधान'', RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 150-154 ttp:// anubooks.com/ ?page_id=2004 Artcile No. 21(RP570)

प्रस्तावना

इन नक्सल वादियों नें प्रारंभ में तो भूस्वामियों औए शोषक वर्ग के खिलाफ हिंसक कार्यवाहियां तथा लूटपाट की, किन्तु सरकार द्वारा इनके खिलाफ कार्यवाहियां प्रारंभ करने के कारण इन्होंने पुलिस एवं प्रशासन को भी निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। 1970–71 में नक्सलवादी हिंसा अपने चरम पर थी इस अवधि में पश्चिम बंगाल, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में कुल मिला कर लगभग 4000 नक्सलवादी वारदातें हुई जिसके बाद सरकार नें 'ऑपरेशन स्तीपल्वेज' नाम से पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा में नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में सेना का सघन अभियान शुरू कर दिया इस ओपरेशन की प्रभावित। के काफी सकारात्मक परिणाम सामनें आये और इस क्षेत्र में नक्सल वादियों का संगठन तहस नहस हो गया चारू मजुमदार के निधन के साथ ही नक्सल वाद के प्रमुख अध्याय की समाप्ति हो गयी तथा संगठन में बिखराव की स्थिति आ गयी 1980 किन्तु इससें प्रदेश आन्ध्र के कोंडापल्ली सीता कोंडापल्ली सीता रमैया के नेतृत्त्व में चिप्लिस वर ग्रुप (IOx) के गठन के साथ ही उस आन्दोलन को फिर से नै ताकत मिली कोंडापल्ली सीता रमिया के के साथ ही साथ गुम्मदी विट्ठल राव जो गदर के नाम से अधिक प्रसिद्ध है ने अपनी कविताओं एवं गीतों के जरिये इस आन्दोलन के पक्ष में व्यापक जनाधार बनाया गदर ने अपने अनेक करांतिकारी लेखक साथियों के साथ मिलकर चूह के संस्कृति मंच जन नाटी मंडली की स्थापना की तःथा एक एसा माहोल तैयार किया जिसनें नक्सली विचार धारा को आमजन की स्वकृति दिलानें में मदद 1992 में आन्ध्र प्रदेश सरकार के PWG के खिलाफ अभियान में कोंडापल्ली सीता रमीय एवं अन्यानेक नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी से इस आन्दोलन को आन्ध्र प्रदेश एवं निकटवर्ती राज्यों में अल्पकालिक झटका लगा दूसरी और बिहार में एक अन्य नक्सली संगठन मओइस्त कम्युनिस्ट सेण्टर एम् सी सी का उदय कन्हाई चेटर्जी के नेतृत्त्व में हुआ जिसने व्यापक पैमाने पर हिंसक वारदातें की बिहार में यह आन्दोलन आर्थिक सामाजिक संघर्ष के साथ–साथ जाती गत विद्वेष और लड़ाई को भी बढ़ावा देता रहा है। यहाँ कुछ स्थानों पर तो एम् सी सी समान्तर सरकारें तक स्थापित कर ली थी।

PWG और एम् सी सी के एल टी टी ई (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) उल्फा (UNITED LIBRATION FRONT OF ASSAM NSCN –I/नेशनल सोसिअलिस्ट काउन्सिल OF नागालैंड ई ध्एम् गुट) के साथ संपर्कों की भी पुष्टि हुई यह उग्रवादी संगठन PWG और MCC को न केवल हथियार और विस्फोटक सामग्री ही उपलब्ध करते है बल्कि इनके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करते रहते हैं।

नई सदी के प्रारंभ में इस आन्दोलन में एक नई गति उस समय आई जब पीपुल्स वर ग्रुप की नौवीं Congresss की बैठक में पार्टी के हथियार बंद भाग का नाम पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी रखा गया तथा इसे आधुनिक हथियारों से लैस करनें, आन्दोलन का विस्तार बढ़ाने क्षेत्र, नेपाल सीमा से लेकर तमिलनाडु तक एक लाल गलियारा रेड कोरिडोर बनानें तथा PWG एवं MCC के एकीकरण का निर्णय लिया इसके परिणामस्वरुप 24 अक्टूबर 2004 को PWG PWG एवं MCC MCC के एकीकरण की औपचारिक घोषणा की गयी इस एकीकृत दल को कमुनिस्ट पार्टी ऑफ

इंडिया (माओवादी का नाम दिया गया इस का नेत्रत्त्व मुप्पल्ला लक्स्मन उर्फ गणपति को सौंपा गया।

इस एकीकरण के साथ इस आन्दोलन का आधार और व्यापक हुआ है तथा अखिल भारतीय क्रांति करी स्वरुप की नीव भी रखी गयी गई है। जिसके अंतर्गत सघन क्रन्तिकारी की क्षेत्र संकल्पना को मूर्त रूप देना प्रमुख है माओवादी संगठनों की नेपाल से लिकर दंद्करान्य क्षेत्र तक एकत्यंत प्रभावी क्षेत्र बनाने की योजना है। इस क्षेत्र पर उनका पूर्ण आर्थिक राजनितिक एवं सैन्य प्रभाव होगा इस ख्सेत्र को आधार क्षेत्र बना कर माओवादी सम्पूर्ण भारत में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। नक्सलियों के एक नए संगठन रिवोलुश्नरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के समूचे उत्तर प्रदेश, उत्तरखंड, पंजाब तथा हरियाणा में पैठ बनाने की योजना बने है तथा इस लक्ष्य बुद्धिजीवियों को इस संगठन की विचार धारा के नजदीक लाना है

कारण :– अब प्रश्न यह उठता है की भारत मैं नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के पीछे क्या कारण रहे हैं यद्यपि नक्सलवादी आन्दोलन का प्रेरणा पुंज सदैव चीन रहा है किन्तु भारत के आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक एवं क्षेत्रिय विषमताओं नें इस आन्दोलन के विकास के लिए उर्वर भूमि प्रदान की है आजादी के बाद गरीबी एवं बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए सरकार नें अनेकों योजनाओं की शुरुआत की किन्तु भ्रष्ट्राचार, लाल फीता शाही, उपेक्षा एवं शुद्र स्वार्थों के चलते सही एवं कार्यान्वन नहीं होने के कारण इन योजनाओं का लाभ कुछ एक लोगों एवं वर्गों तक ही सीमित रहा दूसरी और भूमि सुधर प्रक्रिया को अक्षर शरू लागु करना तो आज भी दिवास्वप्न ही लगता है जिसके फलस्वरूप भूमि हीन लोगों का निरंतर शोषण उनकी नियति बन गया है जब की नक्सलवादियों द्वारा भूस्वामियों की जमीन हड़प कर खेत मजदूरों को तुरंत सौप देने की जानकारियाँ मिलती रही है मन जाता है की PWG नें आन्ध्र प्रदेश में ही लगभग 5 लाख एकड़ भूमि का पुनर्वितरण किया है इससे गरीब तबके को लगता है की जो कम लोकतान्त्रिक व्यवस्था में बैटन और घोषणाओं में होता है वह नक्सलवादी हकीकत में करते हैं परिणाम स्वरुप दलित और शोषित तबके में नक्सलवादी विचार धारा का जबरदस्त असर हुआ है। सदियों से चली आरही प्रभुत्व वर्ग की शोषण की प्रक्रिया आजाद भारत में लोकतान्त्रिक संस्थानों की स्थापना के बाद भी अबाध चलती रही है जिससे दलित और शोषित वर्ग में इन संस्थानों की उपादेयता और सक्षमता के प्रति कभी श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हुई अपितु हुआ यह है की आजादी के तुरंत बाद जमींदारों, सेठ साहूकारों और रजा महाराजाओं ने राजनैतिक दलों का दामन थम कर लोक तांत्रिक संस्थानों में प्रभावी घुसपैंठ बना ली है इस का परिणाम यह हुआ है की आजादी नें वास्तविक लोकतान्त्रिक व्यवस्था को जन्म न दे कर एक छद्म लोकतान्त्रिक व्यवस्था को जन्म दिया जिसे यतो वंचित वर्ग के शोषण को अवरुद्ध करनें के कारगर उपाय किये ही नहीं या किये तो उन्हें पूरे मनोयोग से लागू नहीं किया।

देश की न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति नें भी नक्सलवाद को पनपने में सहायता दी है जहाँ पारंपरिक न्याय वयवस्था में एक वाद को निबटा ने में अनेकों वर्ष लग जाते है वहीं

नक्सलवादी अपनी जन अदालतों के माध्यम से स्थानीय समस्याओं और मुकदमों का त्वरित निबटारा करते है तथा दोषियों को मौके पर ही सजा दे देते हैं कुल मिला कर गरीबों और शोषितों पर निरंतर अत्याचार और साशन एवं प्रशासन की इउसे रोकने में असफलता ने इस विचारधारा को फल्ने फूलने में मदद की इसके लिए किसी भी एक पक्ष को दोश देना बेईमानी होगी समाज अपितु, प्रशासन और व्यवस्था सभी इस स्थिति के लिए दोशी है 2005 नवम्बर की बहुचर्चित जहान्नाबाद जेल ब्रेक के बाद भा का प् (माओवादी) के प्रवक्ता नें कहा था। जब तक गरीबी, शोषण और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा तब तक हमारी ताकत भी बढती रहेगी और हमारी क्रांति भी बड़ती जाएगी नक्सलवादियों के शोषित वर्ग के हितबद्ध ठोस कार्यक्रमों यथा भूमि का पुनर्वितरण खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाना दोषियों पर कर जुरमाना लगाना भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों अधिकारीयों के विरुद्ध कार्यवाही करना जनादालातों का संचालन करना आदि नें इस विचार धारा को जन जन तक पहचानें में मदद की है।

समाधान :– जैसा की पहले ही उल्लेख किया जा चूका है की नक्सलवाद केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है यह मूलत रूप से एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, जिससे निबटनें के लिए सरकार समाज को एक बहुआयामी रणनीति बनानी चाहिए जब की सरकार इससे कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में निबटाने का प्रयास करती रही है वस्तुतः इसके लिए एक पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील सुशासन की जरूरत है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शोषण, अन्याय, अत्याचार एवं सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त करने की दिशा में सर्तक प्रयास करें, कानून व्यवस्था की स्थिति में आमूलचूल सुधर करें जमीन सम्बन्धी विवादों का त्वरित निबटारा करें, भूमि सुधार कानून को अक्षर शुरू लागू करें जन षिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निबटारा करनें के लिए विशेष अदालतों का संगठन करें और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करें नक्सलवादियों के आधार भूत ढांचे एवं कार्यप्रणाली के विरुद्ध एक समन्वित पुलिस कार्यवाही की जनि चाहिए इस हेतु आन्ध्र प्रदेश के ग्रे हौस की तर्ज पर विषेश पुलिस बालों का गठन होना चाहिए तथा विभिन्न प्रभावित राज्यों को संयुक्त टास्क फोर्स बनानी, चौथे पुलिस बल के आधुनिकरण के लिए विषेश प्रयास किये जानें चाहिय क्योंकि नक्सलियों के पास न केवल आधुनिक हथियारों का जखीरा है बल्कि उनकी संरचना एवं सूचना प्रणाली भी आधुनिकतम यंत्रों से लैस हो चुकी है पुलिस एवं अर्ध सिंक बालों के बीच कारगर समन्वय बनाना चाहिए जहाँ तक हो सके इस समस्या से निबटने के लिए सेना की भूमिका को कम से कम किया जाना चाहिए प्राय यह देखा गया है की नक्सलवाद की समस्या से जूंझ रहे राज्यों में इस समस्या से निबटनें की कार्यप्रणाली में एकरूपता और समन्वय का आभाव है इसके लिए सरकार केंद्र को पहल करते हुए एक समन्वित एवं एक रूप कार्यप्रणाली विकसित करनी चाहिए इसके अतिरिक्त नक्सली गुटों के साथ शंति वार्ताओं का आयोजन भी होना चाहिय किन्तु इस शर्त पर की वे हथियार एवं हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हों साथ ही शांतिवार्ता के दौरान अत्यधिक सावधान रहनें की भी जरूरत है की कहीं इस समय का उपयोग नक्सलवादी अपनी सैन्य एवं कार्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए

तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राय शांति वार्ताओं के दौरान पुलिस एवं सेना के अभियान स्थगित कर दिये जाते हैं। इसके लिए सरकारी आसूचना को तंत्र विशेष रूप से सजग रहनें की आवश्यकता है। नक्सल वाद के सामाजिक आर्थिक कारणों से निबटाने की कुंजी सु शासन और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वन में निहित है इस आन्दोलन की प्रकृति और शैली मैं आ रहे परिवर्तनों की पहचान करनी होगी क्योंकि उनका सैन्य कारन बढ़ रहा है और वे उन्नत सैन्य संगठनों में तब्दील होरहे है इस लिए स्थानीय पुलिस व्यवस्था और खुफ़ियों को तंत्र मजबूत बनाना जरूरी हो गया है। इसके लिए नक्सल प्रभावित जिलों में सक्षम अधिकारीयों की तैनाती तथा उन्हें स्थिरता प्रदान करना आवष्यक है, स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना एक दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलु है सरकार को कानून वयवस्था केसाथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर धयन देना होगा तभी हम देष की वर्तमान में सबसे गंभीर समस्या से निबट सकते है।

References

1. Ramakrishnan, Venkitesh (21 September 2005). "The Naxalite Challenge". Frontline Magazine (The Hindu). Retrieved 2007-03-15.

2. Sen, Sunil Kumar (1982). Peasant movements in India: mid-nineteenth and twentieth centuries. Calcutta: K.P. Bagchi.

3. "History of Naxalism". Hindustan Times. 15 December 2005. Archived from the original on 8 February 2011.

4. Handoo, Ashok. "Naxal Problem needs a holistic approach". Press Information Bureau. Retrieved 2009-08-08.

5. "Historic low' in terror, Naxal violence". 31 December 2012. Retrieved 2012-12-31.